भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2926
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

कर्नाटक को स्वीकृत और आवंटित किया गया बजट

2926. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को स्वीकृत एवं आबंटित बजट का शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कर्नाटक राज्य ने सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दिए गए बजट के लेखांकन की निगरानी करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

तथापि, डिजिटल भारत निधि, डीबीएन (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित/संवितरित की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

				करोड़ रुपये में
क्र. सं.	स्कीम का नाम	2023-24	2024-25	कुल
1	भारतनेट	152.96	177.57	330.53
2	4जी सेचुरेशन मोबाइल परियोजना	88.76	105.38	194.14
3	354 सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान	0.24	0.24	0.48
	सकल योग	241.96	283.19	525.15

(ख) और (ग) :

डिजिटल भारत निधि से संवितरित निधियों की निगरानी डिजिटल भारत निधि और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच किए गए करार के निबंधन और शर्तों के आधार पर की जाती है जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शामिल हैं।

*****